enabling import of capital goods at concessional duty for export production, special arrangements for duty free import of raw materials for export production, etc.

वस्त्र मंत्रालय का वार्षिक योजनागत परिव्यय

920. **श्री जीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने वर्ष 1998-99 के लिए वस्त्र मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं हेतु कुल कितना वार्षिक परिव्यय स्वीकृत किया है;

(ख) इसके अंतर्गत वस्त्र उत्पादन एवं निर्यात की अपेक्षित दरें क्या-क्या हैं;

(ग) मंत्रालय ने उपर्युक्त कुल परिव्यय के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कुल कितना वित्तीय प्रावधान रखा है;

(घ) उक्त वर्ष में इन राज्यों की अनुमोदित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके अंतर्गत क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) वर्ष 1998-99 में वस्त्र मंत्रालय के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 240.88 करोड़ रु० है।

(ख) वर्ष 1998-99 में यार्न और फैब्रिक का उत्पादन तथा वस्त्रों के निर्यात मूल्य पिछले वर्ष के स्तर पर बने रहने की संभावना है।

(ग) मंत्रालय के लिए योजना स्कीम वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और राज्य-वार आरक्षण नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1998-99 के लिए महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में चालू योजनाओं की सूची संलग्न विवरण में निर्दिष्ट है।

विवरण

योजनाओं के नाम	महाराष्ट्र	गुजरात
विद्युतकरघा:		
(क) विद्युतकरघा सेवा केन्द्र	प्रचालन में	प्रचालन में
(ख) कम्प्यूटर सहायित डिजाईन केन्द्र	-वही-	-वही-
(ग) विद्युतकरघा बुनकरों के लिए बीमा योजना	-वही-	-वही-
हथकरघा:		
(क) प्रचार एवं प्रदर्शनी	शून्य	प्रचालन में
(ख) बचत निधि योजना	-वही-	-वही-
(ग) कार्यगृह-सह-आवास	-वही-	-वही-
(घ) परियोजना पैकेज	प्रचालन में	-वही-
(ङ) बाजार विकास सहायता	-वही-	-वही-
हस्तशिल्प:		
(क) प्रदर्शनी एवं प्रचार	प्रचालन में	प्रचालन में
(ख) प्रशिक्षण	-वही-	-वही-
(ग) सर्वेक्षण और अध्ययन	-वही-	शून्य
(घ) इम्पोरियम का नवीकरण	शून्य	प्रचालन में

योजनाओं के नाम	महाराष्ट्र	गुजरात
(ङ) डिजाईन विकास	प्रचालन में	-वही-
(च) बाजार विकास	-वही-	-वही-
रेशम उत्पादन:		
(क) राज्यों को विभिन्न प्रकार के शहतूती बैंकों में सुधार लाने के लिए उत्प्रेरक विकास सहायता	प्रचालन में	प्रचालन में
(ख) ऑन-फार्म प्रशिक्षण देने तथा औजारों की आपूर्ति करने के लिए राज्यों को सहायता	-वही-	शून्य
(ग) विस्तार और प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए सहायता	-वही-	-वही-
(घ) राज्यों को मास्टर रीलर सहायता	-वही-	-वही-
ऊन:		
(क) एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	शून्य	प्रचालन में
(ख) मशीन कतरन-सह-प्रशिक्षण परियोजना	-वही-	-वही-

Garment Quota Entitlement

921. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether under pressure from the European Union over the recent controversy on overshooting the 1998 garment quota entitlement, India has agreed to bind import duties on a wide array of textile sector items with the World Trade Organisation; and

(b) if so, what are the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) and (b) No, Sir. In the Indo-EU-MOU on market access for textiles and clothing products signed on 31.12.1994, which provided mutual benefits, Government had agreed, inter-alia, to reduce its import tariffs and bind its tariffs by notifying to the WTO in respect of the textile items listed in the MOU. Different textile products, including fibres, yarn, fabrics, made-ups and garments, and totalling 220 HS lines, are covered under the MOU.

राष्ट्रीय परिधान निर्यात नीति

922. **श्री गोविन्दराम मेघरी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने कोई राष्ट्रीय परिधान निर्यात नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान उपरोक्त नीति को किन-किन पहलुओं के संबंध में कार्यान्वित किया गया है;

(घ) क्या कार्यान्वयन में किन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बाधाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ङ) परिधानों को, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, यू०एस०ए० और कनाडा जो द्विपक्षीय करारों के अनुसार मात्रात्मक प्रतिबंधों के अंतर्गत हैं, निर्यात के संबंध में